

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी- चौद मल वर्मा (आर.एस.)

अपील प्रकरण संख्या: 120/2017

सुरेन्द्र पुत्र रणवीर जाति जाट निवासी 96 हैड तहसील सूरतगढ

बनाम

तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित-

- 1. अधिवक्ता अपीलान्त श्री शिशपाल शर्मा
- 2. राज पैरोकार

दिनांक: 16.02.2018

निर्णय



अपील में अपीलान्त ने कथन किया है कि चक 1 ए.पी.डी के पत्थर नं. 70/324 के किला नं. 3 गां 8, 14 गां 16 व 23, 24 का 3162 है 0 रकबा का नाजायज काश्त का नोटिस मिला इस नोटिस के अभाव में अपीलान्त ने निवेदन किया कि यह रकबा अपीलान्त के पुराना कब्जा काश्त में चला रहा है इस रकबा की सक्षम न्यायालय में पुराना आवंटन की पत्रावली अपीलान्त की जैरकार है। परन्तु अदालत मातहत तहसीलदार सूरतगढ ने जैर अपील आदेश पारित कर अपीलान्त की उक्त रकबा की फसल कुर्क करने कुर्कशुदा फसल निलामी करने व पटवारी हक्का को पैन्टी राशि वसूल करने व अपीलान्त को बेदखल करने कब्जा बहक सरकार लेने का निर्णय दिया है, इस निर्णय में अपीलान्त को चार सजाये एक साथ दे दी है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। प्रार्थी एवं उसके पूर्वजों का इस रकबा पर पिछले 50-55 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है व अपीलान्त के पूर्वजों के फौत हो जाने के पश्चात इस रकबा पर अपीलान्त का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अपील संख्या 120/2017 पर दर्ज किया गया। रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये व पैरोकार राज उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्त ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी एवं उसके पूर्वजों का इस रकबा पर पिछले 50-55 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है व अपीलान्त के पूर्वजों के फौत हो जाने के पश्चात इस रकबा पर अपीलान्त का कब्जा काश्त चला आ रहा है। सक्षम न्यायालय में पुराना आवंटन की पत्रावली जैरकार है। अपीलान्त उक्त रकबा आवंटन का पूरा पात्र है। उक्त रकबा नियमन/आवंटन पश्चात किरते/नियमन राशि डीप्लसी बरों पर जमा करवाने को तैयार है। रकबा मौका पर अराजीराज है तथा मौका पर रकबा एस्केप के नाम दर्ज है व शुद्ध अराजीराज नहीं है।

बहस के दौरान राज पैरोकार ने निवेदन किया कि अपीलान्त ने दिनांक 08.03.2016 को प्रार्थना पत्र पेश कर स्वीकार किया है कि उसने नाजायज काश्त की है तथा आईन्दा नाजायज काश्त नहीं करेगा। अतः प्रार्थी के विरुद्ध की गई नाजायज काश्त की कार्यवाही में उचित तावान से दण्डित कर पत्रावली दाखिल वफ्तार करने का श्रम करे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र से यह साफ पता चलता है कि प्रार्थी के यह ध्यान में था कि उक्त भूमि राजकीय भूमि है परन्तु फिर भी अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि नाजायज काश्त की गई जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। प्रार्थी द्वारा स्वयं उक्त प्रार्थना पत्र में उचित तावान से दण्डित करने हेतु निवेदन किया है। अपीलान्त द्वारा यह अपील कब्जा से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेने व फसल कुर्क कर निलामी के आदेश देने के विरुद्ध पेश की है। इस संबंध में निवेदन है कि जैर अपील निर्णय में दिये गये दण्ड नियमानुसार ही है। फसल कुर्क कर निलामी करने से राजकोष को फायदा होगा। साथ ही अपीलान्त को अतिक्रमी होने के कारण उक्त रकबा से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज की जाकर निर्णय यथावत् रखा जाये। व अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

अपीलान्त द्वारा यह अपील 05.10.2017 को पेश की गई है। अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र में अपीलान्त ने यह कथन किया है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 06.9.2017 को हुई है। जबकि अपीलान्त ने दिनांक 08.03.2016 को ही अधीनस्थ न्यायालय के सक्षम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह माना है कि उसके द्वारा नाजायज काश्त की गई है। व उक्त प्रार्थना में निवेदन किया कि वह आईन्दा काश्त नहीं करेगा तथा तावान कायम किये जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय भी दिनांक 08.3.2016 को ही पारित किया गया है। अपील मीनों एवं सभी तथ्यों के विरुद्ध अवलोकन, मनन से स्पष्ट है कि अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अनभिज्ञ नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ

है तथा अपने मियाद बाबत प्रार्थना पत्र में भी कोई वैशिष्टिक कारण भी जाहिर नहीं किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी किसी सुरेन्द्र के नाम से है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलान्त उक्त प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में मिथ्या कथन कर रहा है। अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। साथ ही इसी आधार पर अपील अपीलान्त भी खारिज की जाती है।

हमने पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन किया, मनन, चिंतन किया। अपील मीमों का भी गहनता से अध्ययन किया। अपील मीमों के बिन्दु संख्या 2, 3, 5, 6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्त को भूमि की स्थिति पता होनें उसके संज्ञान में होते हुए कि भूमि अराजीराज एस्केप के नाम दर्ज है, तो भी अतिक्रमण किया है तथा उक्त भूमि पर उसका विधिक हक-हकूक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ की मूल पत्रावली संख्या 5/16 के पृष्ठ संख्या 3 के अन्त में पटवारी को तावान वसूली एवं अप्रार्थी संख्या 1 (सुरेन्द्र) को प्रश्नगत भूमि से वेदखल कर कब्जा अधिशाषी अभियंता, सिंचाई विभाग, सूरतगढ़ को दिलाने तथा नीलामी की रिपोर्ट बाबत निर्णय किया गया है। पृष्ठ संख्या 6 में गिरदावर हल्का, रामसरा जाखडान को फसल कुर्क कर अपने कब्जे में लेने हेतु तहसीलदार ने निर्देशित किया है। पृष्ठ संख्या 10 में गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 04.3.2016 को विवादित भूमि पर खड़ी फसल की कुर्की की गई है। पृष्ठ संख्या 13 पर पटवारी हल्का घमण्डिया को उक्त प्रकरण में वसूली करने, अतिक्रमी को मौके पर भौतिक रूप से वेदखल कर कब्जा अधिशाषी अभियंता, जल संशाधन विभाग, सूरतगढ़ को सौंपकर पालना रिपोर्ट पेश करने बाबत निर्देशित किया गया है। इसी पत्रावली के अन्तिम पृष्ठ संख्या 14 में तहसीलदार ने भू-अभिलेख निरीक्षक रामसरा जाखडान को फसल नीलामी की रिपोर्ट पेश करने बाबत निर्देशित किया है।

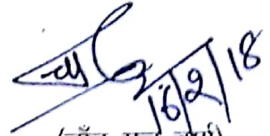
इस प्रकार पत्रावली के समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त पत्रावली क्रमांक 5/16 तहसील सूरतगढ़ में तत्कालीन जिम्मेदार पटवारी हल्का ने अतिक्रमी को भौतिक रूप से वेदखल कर कब्जा अधिशाषी अभियंता, सिंचाई विभाग, सूरतगढ़ को नहीं संभलाया तथा तत्कालीन जिम्मेदार गिरदावर रामसरा जाखडान ने फसल की नीलामी कर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जो सीधे-सीधे राजकोष को हानि है व अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही तथा अतिक्रमी से मिलीभगती है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित पटवारी एवं गिरदावर के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर उच्चाधिकारियों को दो सप्ताह में पेश करे एवं इस न्यायालय को सूचित करे।

निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



  
(चौद मल वर्मा)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
सूरतगढ़